रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122023-250692
CG-DL-E-15122023-250692

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/ अग्रहायण 24, 1945 (शक)
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 15*th December,* 2023/*Agrahayana* 24, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) ACT, 2023

No. 35 OF 2023

[15*th December,* 2023]

An Act further to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 14.

2. In the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 14,— 34 of 2019.

(*i*) in sub-section (*3*), the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided that subject to the provisions of sub-section (*1*) of section 60, on and from the date of commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the figures "107", the figures "114" had been substituted.';

(*ii*) for sub-section (*10*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

'(*10*) In the Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950, under the sub-heading "II. UNION TERRITORIES", against serial number 3 relating to "Jammu and Kashmir", for the entries under columns 2 to 7, the following entries shall respectively be substituted, namely:— 43 of 1950.

1	2	3	4	5	6	7
"3. Jammu and Kashmir	90	7	9	90	7	9".'.

Insertion of new sections 15A and 15B.

3. After section 15 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Nomination of Kashmiri Migrants.

'15A. Notwithstanding anything contained in sub-section (*3*) of section 14, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than two members, one of whom shall be a woman, from the community of Kashmiri Migrants, to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.

Explanation.—For the purposes of this section, the term "Migrant" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*e*) of section 2 of the Jammu and Kashmir Migrant Immovable Property (Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales) Act, 1997. Jammu and Kashmir Act XVI of 1997.

Nomination of displaced persons.

15B. Notwithstanding anything contained in sub-section (*3*) of section 14, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.

Explanation.—For the purposes of this section, the term "displaced person" means any person, who, on account of the setting up of the dominions of India and Pakistan, or on account of civil disturbances or fear of such disturbances in any area of the then State of Jammu and Kashmir presently under occupation of Pakistan, during the years 1947-48, 1965 and 1971, had left or had been displaced due to such disturbances from his place of residence in such area and who has been subsequently residing outside such area and also includes successors-in-interest of any such person.'.

S.K.G. RAHATE,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

MGIPMRND—474GI—15-12-2023.

Kshitiz Mohan

Doc (1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250903
CG-DL-E-26122023-250903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5227] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945
No. 5227] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5458(अ)—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 35) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 दिसम्बर, 2023 का उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 11012/02/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2023

S.O. 5458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023 (35 of 2023), the Central Government hereby appoints the 26th day of December, 2023, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 11012/02/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

7938 GI/2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 35)

[15 दिसम्बर, 2023]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 14 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 में,— 2019 का 34

(i) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही इस उपधारा के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो अंक "107" के स्थान पर अंक "114" रखा गया हो';

(ii) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में, "II. संघ राज्यक्षेत्र" उपशीर्षक के अधीन, "जम्मू-कश्मीर" से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 2 से स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :— 1950 का 43

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	90	7	9	90	7	9"।'

नई धारा 15क और 15ख का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कश्मीरी विस्थापितों का नामनिर्देशन ।

'15क. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के समुदाय से दो से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिनमें से एक महिला होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विस्थापित" पद का वही अर्थ होगा जो जम्मू-कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् विक्रय पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है । 1997 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 16

विस्थापित व्यक्तियों का नामनिर्देशन ।

15ख. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य को जम्मू-कश्मीर विधान सभा में नामनिर्देशित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विस्थापित व्यक्ति" पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना किए जाने के कारण या सिविल उपद्रव या वर्तमान में पाकिस्तान के अधिभोग के अधीन तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी क्षेत्र में ऐसे उपद्रवों के भय के कारण वर्ष 1947-48, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के दौरान ऐसे क्षेत्र में ऐसे उपद्रवों के कारण अपने निवास स्थान को छोड़ दिया था या उससे विस्थापित हो गया था और जो तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र से बाहर निवास

करता रहा है तथा इसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का हित-उत्तराधिकारी भी है ।'।